

संपादकीय

दिल्ली का दम घुटा जा रहा, जनता सांस मांग रही, सरकार का जवाब - पुरानी गाड़ी हटाओ



दिल्ली और अन्य महानगरों में प्रटूषण की समस्या जिस स्तर पर गहराई गई है, उसमें इस पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले उपायों से शायद ही किसी को असहमति होगी। विडंबना यह है कि कई बार किसी समस्या से पार पाने के लिए जिन उपायों का सहारा लिया जाता है, उसकी व्यावहारिकता कठघरे में होती है। दिल्ली में हर अगले साल प्रटूषण के गहराते संकट के सबसे बड़े कारणों में एक बाहों से होने वाले उत्सर्जन को माना गया और इस आधार पर पिछले कुछ वर्षों से सम-विषम जैसे नियम लागू कर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। इसके अलावा, पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने को लेकर नियम-कायदे बनाए गए। हालांकि इसके अपेक्षित नतीजे को लेकर हमेशा संशय रहा। गौरतलब है कि दिल्ली में कुछ दिन पहले यह घोषणा की गई कि पंद्रह वर्ष पुराने पेट्रोल और दस वर्ष पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। साथ ही पेट्रोल पप पर पुरानी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा था। जाहिर है, एक साथ बड़ी तादाद में वाहनों के सड़कों से हटाने की नीति आने पर आम लोगों के बीच व्यापक पैमाने पर आक्रंश का भाव पैदा हुआ और सरकार के इस फैसले पर सवाल उठे कि क्या अकेले इस उपाय से दिल्ली में प्रटूषण की समस्या को खत्म किया जा सकता है। इससे बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका भी प्रभावित हो सकती है। सरकार के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। यह बेवजह नहीं है कि गुरुवार को दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को पत्र लिख कर कहा कि तकनीकी चुनौतियों और जटिल प्रणाली के कारण तथ मियाद पूरी कर चुके वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध लगाना व्यावहारिक नहीं है। यानी फिलहाल पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने की कायद थमती दिख रही है। हालांकि इसे लेकर आम लोगों के बीच जैसी प्रतिक्रिया सामने आई, उसके बाद यह देखने की बात होगी कि इस मसले पर सरकार क्या रुख अपनाती है। माना जाता है कि तकनीकी रूप से पुराने, अधिक ईंधन खपत करने और खराब रखरखाव वाले वाहनों से प्रटूषण ज्यादा फैलता है और ऐसी स्थिति में ऐसे वाहन पर्यावरण और लोगों की सेहत के लिए जोखिम भरे हो सकते हैं। मगर ऐसे सवाल भी उत्तर रहे हैं कि प्रटूषण फैलाने के लिए किसी वाहन की उम्र को पैमाना माना जाना चाहिए। या फिर प्रटूषित पदार्थ उत्सर्जित करने की जांच के आधार पर वाहन के दुरुस्त होने के बारे में तय किया जाएगा। अगर कोई पुराना वाहन पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित है, तो उसकी उम्र को ही अकेला मानदंड क्यों बनाया जाना चाहिए? जहां तक दिल्ली का सवाल है, यह न केवल अन्य राज्यों के कुछ शहरों को मिला कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, बल्कि दिल्ली के अलावा अन्य शहरों में पुराने वाहनों को लेकर अलग नियम हैं। साथ ही दिल्ली में असापस के राज्यों से हर रोज ऐसे हजारों वाहन आते-जाते हैं, जो पुराने हो सकते हैं, हालांकि उन्हें दूसरे राज्यों में प्रटूषण जांच के पैमाने पर दुरुस्त माना जाता है। शायद इसीलिए ऐसे सवाल उत्तर रहे हैं कि जिन वाहनों को दूसरे राज्यों में प्रटूषण फैलाने की क्षमता पर सुरक्षित माना जाता है, उन्हें दिल्ली के लिए मुसीबत क्यों माना जाना चाहिए! या फिर अन्य राज्यों के वाहनों के लिए अलग नियम कैसे सही हैं? निश्चित रूप से प्रटूषण एक गंभीर समस्या है। मगर इससे निपटने के तौर-तरीकों में अगर विरोधाभास होगा तो उसकी व्यावहारिकता कसौटी पर रहेगी।

इन दिनों जब पूरी

पुनर्वा युद्ध का दृष्टाता स
अभिशप्त दिखती है तो
फिर अमन की तलाश में
कौन से रास्ते तलाश किए
जाएं, ताकि मानव जीवन
सुरक्षित रह सके? असल
में यही है जिंदगी के लिए
शांति की अंतर्रूढ़ि का वह

आयाम जो जिंदगी को
संतुष्टि के साथ शांति के
मार्ग पर चलते हुए नई

आंतर्दृष्टियों के नए
इंद्रधनुषों को खोलता है।
शांति की आंतर्दृष्टि का
सीधा अर्थ है जीवन में
शांति की गहराई को
समझना और जीने के
नेतृत्व तथा प्रभावों को
जानना। मगर यह उन
स्थितियों पर निर्भर करता
है कि जिस समाज में हम
जी रहे हैं, उसमें
सामाजिक आर्थिक और
मानव प्रकृतियों की
प्रक्रिया कैसी है।

अब एआई के हवाले जिंदगी, टेक्नोलॉजी बन गई है सांस, ऐसे में बेघैन मन को शांति कहाँ मिले? ऐप्स की दुनिया में इंसान अकेला



तरह से जंगल, जल और वायु को प्रदूषित किया है, वह आने वाले वर्षों में हमारे उस प्रश्न पर झ़गड़ों का कारण बनेगा। इसमें असली लड़ाई अब सांसों के लिए वायु प्राण की शांति में जीने की लालसा में होगी। जल की बूंद-बूंद के लिए लड़ाई के मुहाने पर पहुंचा हुआ विश्व शांति और युद्ध के बीच क्या चुनना चाहता है? दरअसल, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, वह जटिल, विरोधाभासी और परस्पर छोटे युद्ध तथा नफरती बयार से भर गई है। यह तब हो रहा है, जब पूरी दुनिया ज्ञान के नए आकाश को छू रही है। इस आसमान में आदमी प्रकृति तथा ब्रह्मांड के भेद को तो भेदना तो चाह रहा है, पर उसने अपनी भंग शांति में सब कुछ खो दिया है। संघर्षों के कर्म को समझना जीने के नए रास्तों को तय करने और ध्यान, योग की प्रवीण प्रवृत्तियों को सहज पूर्णता के कारण एक नई संस्कृतियों के दौर को स्वीकार करने, सम्मान करने तथा शांति से जीने की एक परंपरा हमारे समाज में है। यही समाज की खूबसूरती है, जिसमें विभिन्न समुदयों और विभिन्न रंग-रूप तथा भाषाओं के रंग-बिरंगे संजाल में लोग सदियों से रह रहे हैं। यह अलग बात है कि गलामी का भाव अपने जीने के अस्तित्व और युद्ध के दर्शन ने हमेशा इस धरती पर शांति को तार-तार किया है, लेकिन भारतीय जनमानस में करुणा, सहानुभूति, आत्म जगस्कता, विचारों तथा भावनाओं को ध्यान के जरिए नियंत्रित करना दरअसल शांति के लिए आत्म चिंतन की दूरदृष्टि है। इसके समझने की आज जितनी आवश्यकता है और शांति की प्रासारिकता के अर्थ जितने प्रासारिक आज हैं, उनमें मन को संभालने के सबालों को ध्यान में सुलझा दिया गया है। इन दिनों दुनिया में जो कुछ हो रहा है, वह अंतर्मुखी होकर अपने अंहकार से मुक्त आदमी को इस तेज भागते हुए विश्व की नई परिकल्पना में शांति की गुंजाइश से भर सकता है। यही जीवन जीने की एक नई दिशा का रस्ता है। आज दुनिया विरोधाभास, नए उपभोक्तावाद और आधासी दुनिया की नई परिकल्पना से नहीं, उसके डरावने यथार्थ से ज़ूझ रही है। मन-मस्तिष्क की शांति और आत्मचिंतन की अंतर्दृष्टि ही इससे बचाव का रस्ता है जो हमें शांति समुद्धि और उस सुख की ओर ले जा सकता है, जिसमें जीवन की अंतर्दृष्टियों के साथ चलते हुए हमें एक बेहतर कल की पीढ़ी के लिए एक सुंदर दुनिया की रूपरेखा तथा नई संरचना की ओर ले जा सकता है। हमारे यहां सभी धर्मों-परंपराओं में शांति का बखान है और सभी के लिए एक अरदास की आत्म दृष्टि और सकारात्मक जीने का खला हुआ रस्ता है। एक ऐसा भाईचारा और ऐसी परिकल्पना का 'जोग-संजोग' का शांति-समय है, लेकिन यह भी सच है कि इस अंतर्दृष्टि में शांति पाने के जितने तरीके हमारे इतिहास और शास्त्रों में दर्शाए गए हैं, उनमें मन को संभालने के सबालों को ध्यान में सुलझा दिया गया है। इन दिनों दुनिया में जो कुछ हो रहा है, वह अंतर्मुखी होकर अपने अंहकार से मुक्त आदमी को इस तेज भागते हुए विश्व की नई परिकल्पना में शांति की गुंजाइश से भर सकता है। यही जीवन जीने की एक नई दिशा का रस्ता है। आज दुनिया विरोधाभास, नए उपभोक्तावाद और आधासी दुनिया की नई परिकल्पना से नहीं, उसके डरावने यथार्थ से ज़ूझ रही है। मन-मस्तिष्क की शांति और आत्मचिंतन की अंतर्दृष्टि ही इससे बचाव का रस्ता है जो हमें शांति समुद्धि और उस सुख की ओर ले जा सकता है, जिसमें जीवन की खोज में जिंदगी बची रहे। यही सबाल आज सबसे बड़ा है, जिसके लिए यह काँशियों पूरी दुनिया में हो रही है, ताकि जिंदगी की युद्ध की तबाही से बचाया जा सके और आत्मचिंतन की शांति की अंतर्दृष्टि से आने वाली नस्तों के लिए इस सं-बिरंगे विश्व को संग्रहित रखा जा सके।

विश्व शांति के लिए भी खतरा है पाकिस्तान, सामने आई पड़ोसी देश की मंशा

पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत-पाकिस्तान के संबंधों को प्रभावित किया है। हमले में पर्यटकों की धार्मिक पहचान पूछकर हत्या की गई। लश्कर के संगठन टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली। इस घटना का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को अस्थिर करना था। भारत ने अर्थिक और कूटनीतिक कदम उठाकर पाकिस्तान को जवाब दिया। पहलगाम के आतंकी हमले ने द्विपक्षीय समीकरण ही नहीं, बल्कि समूचे दक्षिण एशिया में संबंधों के तानेबाने को प्रभावित किया है। इस हमले ने आतंक की नीति को जारी रखने वाली पाकिस्तानी मंशा को प्रकट किया था। पर्यटकों से उनकी मजहबी पहचान पूछकर की गई हत्याओं को लश्कर के पिछू संगठन द रेजिस्टरेस फँट यानी टीआरएफ ने नेतृत्व की हरी झंडी के बिना ऐसे किसी

हमले का अंजाम दिया गया हांगा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने आर्थिक, कूटनीतिक और सामरिक मोर्चों पर बहुत काशर कदम उठाए और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। दूसरी ओर, पाकिस्तान लकीर पीटने वाले दैंसें पर चलते हुए बस शेखी बधारता रहा। भारत ने जहां सिंधु जल समझौते को ढंडे बस्ते में डालकर पाकिस्तान और उसकी आर्थिकी की कमर तोड़े वाला दांव चला, वहीं पाकिस्तान शिमला समझौते से पीछे हटने का निर्धारक रण अलापता रहा। कश्मीर में दशकों की अस्थिरता से उड़बरते हुए पटरी पर एक रही पर्यटन गतिविधियां आतंकी हमले के बाद फिर से अनिश्चितता के भंवर में फंस गई हैं। हालांकि इसका आर्थिक खामियाजा जम्मू-कश्मीर से परे सम्पर्च दक्षिण

पश्चिमा को भुगताना पड़ रहा है। इस पश्चात्तभूमि में भारत-पाकिस्तान, दोनों ने आपार, निवेश और बीजा आदि के दोरों पर जो कदम उठाए हैं, उससे द्वितीय सहयोग के साथ ही आर्थिक-आयापारिक गतिविधियों पर भी ग्रहण नगा है। इस तरह एक देश की आतंक परम्पराकृति नीतियों की कीमत पूरे क्षेत्र को अपनी शांति एवं समृद्धि गांवाने के रूप में चुकानी पड़ रही है। यहां तक कि पाकिस्तान के इस रखये का दंश वहां की जनता को भी भुगताना पड़ रहा है। उसे फर्जी राष्ट्रवाद की घुटी पिलाई जा रही है। भले ही पाकिस्तान खुद को आतंक से पीड़ित दिखाने का प्रयास करता रहे, लेकिन उसकी पहचान आतंक से निपटने में शिथिलता दिखाने वाले देश की ही है। करीब ढाई माह पहले ने पहलगाम हमले ने आतंकी गतिविधियों के मामले में पाकिस्तान लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंताओं को सिरे से उभारने का काम किया है में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में वाली एफएटीएफ जैसी संस्था समझ भी पाकिस्तान पर अंकुश तक दबाव बढ़ागा। इससे पाकिस्तानी छवि और खराब होगी। आर्थिक विकास को लेकर उसकी उम्मीदों को पलीता लगेगा। पहलगाम हमले पाकिस्तान के आतंकी चरित्र में खतरनाक बदलाव का भी परिचय है। 2001 की शुरुआत से पाकिस्तान आतंकियों ने मुख्य रूप से क्षेत्र को निशाना बनाते हुए सैन्य विजयों पर ही हमले किए। अनुच्छेद 37 समाप्ति के बाद पहलगाम हमले कश्मीर में हुई पहली बड़ी आतंकी वारदात रही। हिंदुओं को निशाना बनाते ही अपनी आतंकी विजयों को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंताओं को सिरे से उभारने का काम किया है।

के पीछे भी कृतिस नोच एकदम स्पष्ट रहा कि देश में सामाजिक वैमनस्य बढ़े और कश्मीर में सरकार का विकास एजेंडा परी से उतरे। भारत ने इसे बखूबी समझा। इसका असर हमले के बाद की प्रतिक्रिया में भी झलका। भारत ने बहुसंरीय रणनीति अपनाते हुए खुफिया मर्चें को और चाकचाबंद किया, जमीनी स्तर पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती बढ़ाई और किसी भी संभावित आतंकी हमले को निस्तेज करने के लिए अभियान तेज किए, विशेष तौर पर अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर। चूंकि जम्मू-कश्मीर में अभी भी सैकड़ों पाकिस्तान समर्थक आतंकी सक्रिय हैं, इसलिए सुरक्षा बलों की चुनौती काफी कड़ी होने वाली है। इस समय भले ही दोनों देशों के बीच युद्धविराम जैसी स्थिति हो, लेकिन पाकिस्तान अपने आतंकी पिंडों को एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा। भारत ने जिस तरह सिंधु जल सम्पत्तै को स्थगित रखने की दृढ़ता दिखाई है, उसके चलते इसकी भरी-पूरी आशंका है कि आतंकी जम्मू-कश्मीर में किसी अहम इन्फास्ट्रक्चर ढांचे को निशाना बनाएं ताकि भारत सरकार कुछ दबाव में आए और कश्मीर का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय पटल पर छाए। भारत ने इरादे एकदम स्पष्ट कर दिए हैं कि भविष्य में कोई आतंकी हमला युद्ध के लिए उक्साने वाले कृत्य के रूप में देखा जाएगा। किसी हमले की सूरत में दोनों देश फिर से आमने-सामने आ सकते हैं। यह भी एक पहलू है जो पाकिस्तान की नापाक कश्मीर नीति से जुड़ा है। भारत के दृष्टिकोण से पहलगाम हमला केवल एक त्रासदी भर नहीं, बल्कि एक निर्णायक मोड़ रहा। ऐसा मोड़, जिसने भविष्य में किसी भी पाकिस्तानी आतंकी कृत्य से निपटने की उसकी दिशा को निर्धारित किया है। पाकिस्तान के आतंकी चरित्र ने न केवल दक्षिण एशिया की शांति में खलल डाला है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी वह नासूर बन गया है। उसके साथ कूटनीतिक सक्रियता का समय भी अब निकल गया। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी ढांचे को ध्वस्त किए बिना दक्षिण एशिया में शांति संभव नहीं। समय आ गया है कि पाकिस्तान को केवल पहलगाम के लिए ही नहीं, बल्कि दशकों से चले आ रहे छद्य युद्ध में गंवाई हर एक जान के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह बनाकर न्याय के कठघरे में खड़ा किया जाए।

महाराष्ट्र के पुणे में खुद
को 'कृतियर डिलीवरी
एंजेंट' बता कर एक
व्यक्ति ने जिस तरह के
अपराध को अंजाम
दिया, उसने शहरों-

डिलीवरी एजेंट बनकर घर में घुसा, लड़की से बलात्कार किया और बोला- फिर आऊंगा, किसी को बताया तो फोटो वायरल कर दूंगा



की शक्ति में तब्दील हो सकता है। अस्पताल के सघन चिकित्सा कक्ष में उपचाराधीन युवती का कोई कैसे यौन उत्पीड़न करने का साहस कर लेता है? पुणे की आईटी पेशेवर युवती से बलात्कार करने वाला जब यह कहता है कि वह दोबारा आएगा, तो इससे सांतित होता है कि आपराधिक मानसिकता के किसी व्यक्ति का दुस्साहस स्त्रियों के खिलाफ मनमानी करने से आगे बढ़ कर उनके आस्तम्भान्त को गहरी ठेस पहुंचाने तक पहुंच गया है। यह न केवल कानून व्यवस्था के नाकाम होने का सबूत है, बल्कि हमारी सामाजिक जागरूकता भी कठघरे में है। यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि यौन हिंसा के ज्यादातर मामलों में इंसाफ मिलने की हकीकत क्या है। ग्रामीण इलाकों में आमतौर पर ऐसे मामलों को दबाने और रफा-दफा करने की कोशिश होती है। ऐसे में अपराधियों का दुस्साहस बढ़ता है। जबकि महिलाओं के लिए अपने खिलाफ ऐसे अपराध छिपाने का मामला नहीं होना चाहिए। अधिकतर अपराधी स्त्री की इसी भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं के यौन उत्पीड़न का वीडियो बना कर उसे प्रसारित कर देने और पीड़िता को मुंह बद रखने की धमकी देने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। यह नई अपराधिक प्रवृत्ति है, जिससे निपटने के लिए ऐसे अपराधिक खिलाफ मुखर होना पड़ेगा।

हिमाचल प्रदेश के
मंडी जिले में बादल
फटने से जो जन-धन
हानि हुई, वह यही
बता रही है कि अपने
देश में और विशेष
रूप से पर्वतीय
इलाकों में बरसात के
दिनों में कैसी विषम
परिस्थितियां पैदा हो
जाती हैं। ये केवल
इसलिए नहीं पैदा
होतीं कि ज्यादा वर्षा
हो गई, बाढ़ आ गई
या भूस्खलन हो
गया। ऐसी
परिस्थितियां इसलिए
भी पैदा होती हैं,
क्योंकि सरकारी एवं
गैर सरकारी निर्माण
कार्यों की गुणवत्ता
का स्तर बहुत ही
घटिया है।

घटिया निर्माण का नतीजा, सरकारों को ध्यान देने की जरूरत



कराए गए निर्माण कार्य की गुणवत्ता बेहतर होती है। इसीलिए वहां हादसे और उनमें जान गंवाने वाले लोगों की संख्या कम होती है। पता नहीं क्यों हम विकसित देशों से कुछ सीखने से क्यों इन्कार कर रहे हैं? इस इन्कार के लिए राज्यों और केंद्र सरकारों के साथ उनकी नौकरशाही सीधे तौर पर जिम्मेदार है। बुनियादी ढांचे के निर्माण से जुड़े सरकारी विभाग भयंकर किस्म के भ्रष्टाचार से ग्रस्त हैं। इसी कारण नए बने भवन में लीकेज होने लगता है और पुल उद्घाटन से पहले ही ढह जाते हैं। इस सच से पहले की नीति नियंता भी अवगत थे और वर्तमान के भी। अच्छा हो कि वे चेत जाएं और निर्माण कार्यों के लिए बनाए गए मानकों का पालन सुनिश्चित कराएं। इससे ही सरकारी के साथ-साथ निजी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता भी सुधरेगी। समझना कठिन है कि इस जरूरी काम को प्राथमिकता देने में क्या कठिनाई है?

